पूरा बेंच

प्रेम चंद पंडित, एस.एस. संधावालिया और भोपिंदर सिंह ढिल्लों,जे.जे. के समक्ष

प्रेम नाथ भल्ला,-याचिकाकर्ता।
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1968 की सिविल रिट संख्या 3395

18 अगस्त, 1870.

पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम (1931 का II)-धारा 3 (1) 3 (4) और 3 (7)-एक निश्चित अवधि के लिए धारा 3 (1) या 3 (4) के तहत नियुक्त नगरपालिका समिति के कार्यकारी अधिकारी-राज्य सरकार-क्या ऐसे अधिकारी को प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना अवधि की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं-ऐसे नियम-चाहे धारा 7 में निहित हो(1)

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पंजाब नगरपालिका (कार्यपालक अधिकारी) अधिनियम, 1931 की धारा 3 की उपधारा (7) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (4) दोनों के अधीन की गई नियुक्तियों को नियंत्रित करती है। इनमें से किसी भी उप-धारा के तहत नियुक्त कार्यकारी अधिकारी को सरकार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। उनका कार्यकाल कोई नौकरी नहीं है। जब कोई कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति स्वीकार करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि भले ही नगरपालिका समिति उसे एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त कर रही हो, फिर भी सरकार उसकी नियुक्ति के 15 दिनों के बाद भी उसे किसी भी समय हटाने की हकदार है। इन परिस्थितियों में, वह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे पूरी अवधि के लिए पद का अधिकार है। यदि वह जानता है कि उसकी सेवाओं को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, तो उसे कोई शिकायत नहीं हो सकती है यदि राज्य सरकार द्वारा उसके खिलाफ उप-धारा (7) के तहत बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए कार्रवाई की जाती है। वह यह नहीं कह सकते कि उन्हें क्यों और किस आधार पर हटाया जा रहा है और ठीक उसी कारण से वह यह भी नहीं कह सकते कि उन्हें उनके पद से हटाने से पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था। उन्हें अपनी नियुक्ति के समय निर्धारित पूरी अवधि के लिए इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तभी लागू होते हैं जब किसी को किसी पद का अधिकार मिलता है और भले ही उसकी नियुक्ति की शर्तों में यह नहीं कहा गया हो कि उसकी सेवाओं को समाप्त करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, फिर भी उसे पद से बाहर जाने के लिए कहने से पहले ऐसा नोटिस दिया जाना चाहिए। उस स्थिति में, उन्हें सरकार से यह पूछने का अधिकार है कि उनकी सेवाओं को क्यों छोड़ा जा रहा है। जब वह नियुक्ति स्वीकार करता है, तो वह और सरकार दोनों जानते हैं कि उसे उस पद पर बने रहने का अधिकार है और यदि यह एक कार्यकाल की नौकरी है, तो दोनों पक्षों को पूरी तरह से एहसास होता है कि उसे एक विशेष अवधि के लिए वहां रहना होगा। लेकिन, दूसरी ओर, यदि शुरुआत में ही उसे बताया जाता है कि हालांकि उसे एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जा रहा है, फिर भी सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान उसकी सेवाओं को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, तो वह तब शिकायत नहीं कर सकता है कि उसकी सेवाओं को पहले क्यों दिया जा रहा है। अतः राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 (7) के अधीन अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन नियुक्त नगरपालिका समिति के किसी कार्यपालक अधिकारी को उसकी नियुक्ति की अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राकृतिक न्याय के नियमों का अनुपालन किए बिना ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्रदान किए बिना हटा सकती है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अधिनियम की धारा 3 (7) में निहित नहीं हैं।

(पैरा 1 और 10)

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरबंस सिंह और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एस. संधवालिया की खंडपीठ द्वारा 19 नवंबर, 1969 को मामले में शामिल कानून के दो कानूनी प्रश्नों के निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा गया

मामला। माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद पंडित, माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एस. संधवालिया और माननीय न्यायमूर्ति श्री भूपिंदर सिंह ढिल्लों की पूर्ण पीठ ने 18 अगस्त, 1970 को उन्हें भेजे गए कानूनी प्रश्नों का निर्णय लिया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में अनुरोध किया गया है कि 24 अक्टूबर, 1968 के याचिकाकर्ता को हटाने के आदेश को निरस्त करते हुए प्रमाण पत्र, परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से ए. एल. बहल और अधिवक्ता टी. एस. दोआबिया के साथ एच. एल. सरीन।

जे. एन. कौशल, महाधिवक्ता, हरियाणा और आर. एन. मित्तल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थियों की ओर से।

पूर्ण बेंच का निर्णय

पंडित, जे. -विधि के निम्नलिखित दो प्रश्नों को निर्णय के लिए हमें भेजा गया हैः -

(1) क्या राज्य सरकार पंजाब नगरपालिका (कार्यपालक अधिकारी) अधिनियम, 1931 की धारा 3 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन नियुक्त किसी नगरपालिका समिति के कार्यपालक अधिकारी को प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना उसकी नियुक्ति की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर प्रदान किए बिना हटा सकती है?

(2) यदि पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है तो ऐसे मामले में प्राकृतिक न्याय के नियमों की क्या अपेक्षाएँ हैं?

(2) इस संदर्भ को जन्म देने वाले तथ्य ये हैं -पी. एन. भल्ला को पंजाब राज्य द्वारा पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम, 1931 की धारा 3 के तहत नगरपालिका समिति, कैथल के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 11 अगस्त, 1951 को कार्यभार संभाला। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस पद पर कब्जा करना जारी रखा और बाद में, नगर समिति की सिफारिश पर, उनकी नियुक्ति को अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत 12 अगस्त, 1966 से प्रभावी पांच साल की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। 10 सितंबर, 1968 को पी. एन. भल्ला को उप-मंडल अधिकारी, कैथल के माध्यम से एक टेलीफोनिक संदेश प्राप्त हुआ कि श्री वी. पी. धीर, उप-निदेशक, स्थानीय निकाय (शहरी) हरियाणा, भल्ला, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समिति के कुछ सदस्यों के खिलाफ की गई कुछ शिकायतों की जांच करने के लिए कैथल पहुंचेंगे। श्री धीर उसी दिन 4.00 p.m. पर पहुंचे और उन्होंने एक पेपर ('X' चिह्नित) सौंपा, जिसमें 25 आरोप थे, जिनमें से नौ भल्ला के खिलाफ, 13 समिति के मामलों के संबंध में और दो नगर आयुक्तों के खिलाफ थे। 11 सितंबर, 1968 को श्री धीर ने कहा कि उन सभी आरोपों की जांच और संबंधित नगरपालिका की फाइलें भी भल्ला से ली गई थीं। फिर वह अगले दिन 9.00 a.m पर चला गया। भल्ला का मामला यह है कि श्री धीर ने अपनी अनुपस्थिति में कुछ गवाहों से पूछताछ की और उनसे जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उन पर कोई आरोप पत्र नहीं चलाया गया, उनका बयान दर्ज नहीं किया गया और उन्हें कोई बचाव पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। श्री धीर के अनुसार, हालांकि, उन्होंने कुछ गवाहों से पूछताछ की, लेकिन भल्ला की उपस्थिति में। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भल्ला द्वारा सबूत पेश करने के किसी भी अनुरोध को उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। भल्ला के अनुसार, उन्हें गवाहों से जिरह करने के लिए निष्पक्ष और पूर्ण अवसर दिया गया था। उन्हें अपना बयान देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए और उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने 16 सितंबर, 1968 को अपना विस्तृत स्पष्टीकरण भेजा, जिस पर श्री धीर ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते समय विधिवत विचार किया। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि भल्ला को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया था, क्योंकि इस तरह की पूछताछ करते समय ऐसा करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। 24 सितंबर, 1968 को भल्ला को कार्यकारी अधिकारी के पद से हटाने का निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः -

"हरियाणा के राज्यपाल ने करनाल जिले में कैथल नगरपालिका समिति के कार्यकारी अधिकारी श्री प्रेम नाथ भल्ला को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है।"

(3) इसके बाद, 6 नवंबर, 1968 को, भल्ला ने अपने निष्कासन के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। इस याचिका को एक खंड पीठ में स्वीकार कर लिया गया और फिर इसे न्यायमूर्ति हरबंस सिंह और संधावलिया के समक्ष रखा गया।

(4) विवादित आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि हरियाणा की वित्त मंत्री श्रीमती ओम प्रभा जैन के कहने पर पारित आदेश दुर्भावनापूर्ण था। लेकिन उस मामले में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मुद्दा हमारे सामने नहीं है।

(5) याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि उसे उस अवधि की समाप्ति से पहले हटा दिया गया था, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, बिना किसी उचित कारण के। उन पर कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया था, कोई नियमित जांच नहीं की गई थी, उनकी उपस्थिति में गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी और उन्हें उनसे जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया था। उन्हें बचाव में सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें कभी सूचित नहीं किया गया कि श्री धीर द्वारा की जा रही जांच यह पता लगाने के लिए थी कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं।

(6) दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 3 (7) के तहत, सरकार के पास कोई कारण बताए बिना और ऐसी कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का कोई अवसर दिए बिना कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने या पद से हटाने की निरंकुश शक्ति थी। यह भी कहा गया कि कम से कम तत्काल मामले में याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया था। उनके तर्क के समर्थन में, राज्य ने किशोरी लाई बत्रा बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य,ए. आई. आर 1958 पी.बी. 402 मामले में इस न्यायालय के एक पीठ के फैसले पर भरोसा किया। वहाँ हेडनोट्स (डी) और (ई) में कहा गया थाः -

"पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम, 1931 के तहत नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी न तो सरकार का सेवक है और न ही पंजाब नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त एक नगरपालिका सेवक है, लेकिन वह उस कानून का एक हिस्सा है, जिसके तहत उसे नियुक्त किया गया था और उसकी नियुक्ति, सजा, निलंबन या निष्कासन को नियंत्रित करने वाले किसी भी मामले के लिए उस क़ानून या उसके तहत बनाए गए नियमों से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया उस अधिनियम में निर्धारित की गई है, पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 240 (1) के खंड (एन) के तहत बनाए गए कोई भी नियम उस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, या अधिनियम की धारा 3 (7) के तहत की गई किसी भी कार्रवाई पर लागू नहीं हो सकते हैं।

इसके विपरीत संविदात्मक या वैधानिक प्रावधान के अभाव में, स्वामी को अपने सेवक की सेवाओं को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार निहित है और वही नियम स्थानीय अधिकारियों के अधिकारियों पर लागू होता है जिन्हें बिना किसी सूचना या सुनवाई के किसी भी समय हटाया जा सकता है। उस अधिकार को केवल एक अनुबंध या इसके विपरीत वैधानिक प्रावधान द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

माना गया कि पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम, 1931 के तहत नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना हटाना अवैध या कार्रवाई योग्य नहीं था।"

(7) कुछ निर्णयों को नोटिस करने के बाद, डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों की राय थी कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि के. एल. बत्रा (1) मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि पहले भी एक रिट याचिका के फैसले के खिलाफ एक लेटर्स पेटेंट अपील में, जिसे के. एल. बत्रा के मामले को देखते हुए खारिज कर दिया गया था (1) इस सटीक मामले को पूर्ण पीठ को भेज दिया गया था। लेकिन चूंकि अपील निष्फल

हो गई थी, इसलिए पूर्ण पीठ ने इस प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया। इन परिस्थितियों में, विद्वान न्यायाधीशों ने उपरोक्त दो कानूनी प्रश्नों को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इस तरह यह मामला हमारे सामने आया है।

(8) हमें निर्दिष्ट पहले प्रश्न के निर्धारण के लिए, अधिनियम की धारा 3 के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है।

"(1) इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद! नगरपालिका अधिनियम की धारा 26 और 27 में, समिति, उस समय के लिए समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पाँच-आठवें भाग द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्ताव द्वारा, एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में, जिस पर कोई अन्य कार्य नहीं किया जा सकता है, धारा 1 की उपधारा (2) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर, राज्य सरकार के अनुमोदन से, एक व्यक्ति को कार्यकारी अधिकारी के रूप में, पांच साल की नवीकरणीय अवधि के लिए, सभी भत्तों सहित एक हजार पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं वेतन की दर पर, जो वह उचित समझे, नियुक्त करेगीः

* * * *

(2) यदि किसी कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में किसी अभ्यर्थी द्वारा विहित पाँच-आठवां बहुमत प्राप्त करने में विफलता के कारण नियुक्ति का प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है, तो अध्यक्ष, लिखित रूप में की गई मांग पर, समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम नहीं, चौदह दिनों के भीतर आयोजित होने वाली एक और बैठक बुलाएगाः

बशर्ते कि ऐसी बैठक धारा 1 की उपधारा (2) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर आयोजित की जाएगी।

(3) * * * *

(4) यदि समिति धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर किसी कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करने में विफल रहती है तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को समिति के कार्यपालक अधिकारी के रूप में ऐसी मासिक वेतन दर पर, जो सभी भत्तों सहित 1,500 रुपये से अधिक न हो, जो वह ठीक समझे, पांच वर्ष से अनधिक की नवीकरणीय अवधि के लिए नियुक्त कर सकती हैः

(5) * * * *

(6) * * * *

(7) कार्यपालक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय निलंबित या पद से हटाया जा सकता है और यदि समिति की बैठक में उसके निलंबन या निष्कासन के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में उसके निलंबन या निष्कासन के पक्ष में समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पाँच-आठवें हिस्से के पक्ष में मतदान किया जाता है, तो उसे इस प्रकार निलंबित या हटा दिया जाएगा, और यदि कार्यपालक अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है तो समिति राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी व्यक्ति को कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(8) * * * *

(9) * * * *

उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका समिति, राज्य सरकार के अनुमोदन से, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के उपबंधों को उस नगरपालिका तक विस्तारित करने की अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर, किसी व्यक्ति को पांच वर्ष की नवीकरणीय अवधि के लिए समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पाँच-आठवें भाग द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्ताव द्वारा कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। उपधारा (2) के अधीन यदि बैठक में नियुक्ति का संकल्प पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति अपेक्षित पाँच-आठवां बहुमत प्राप्त नहीं कर सका है, तो बैठक का अध्यक्ष सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई की मांग पर 14 दिनों के भीतर उसी उद्देश्य के लिए एक और बैठक बुलाएगा। दूसरी बैठक भी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर उस नगर पालिका को अधिनियम का विस्तार करने के लिए आयोजित की जाएगी। उप-धारा (4) के अनुसार, यदि समिति तीन महीने के भीतर किसी कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार द्वारा उक्त नगरपालिका को अधिनियम का विस्तार करने की अधिसूचना जारी होने की तारीख से राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को समिति के कार्यकारी अधिकारी के रूप में पांच साल से अधिक की नवीकरणीय अवधि के लिए नियुक्त कर सकती है। उपधारा (7) के अधीन कार्यपालक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय निलंबित या पद से हटाया जा सकता है और यदि समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पाँच-आठवें हिस्से के निलंबन या निष्कासन के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में निलंबन या निष्कासन के पक्ष में मतदान किया जाता है, तो कार्यपालक अधिकारी को इस प्रकार निलंबित या हटाया जाएगा।

(9) सवाल का जवाब नं. 1 उपधारा (7) के हस्तक्षेप पर निर्भर करेगा। उपखंड को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग के तहत, राज्य सरकार किसी भी समय स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी कार्यकारी अधिकारी को निलंबित या पद से हटा सकती है। दूसरे भाग के तहत, जब समिति समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पाँच-आठ सदस्यों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है कि निष्पादक अधिकारी को निलंबित या हटाया जा सकता है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार को तदनुसार आदेश देना होगा। तत्काल मामले में, यह सामान्य आधार है कि समिति ने याचिकाकर्ता को हटाने के लिए आवश्यक बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था। यह विवादित आदेश राज्य सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया था। इसलिए, वर्तमान मामले में उपधारा (7) का पहला भाग लागू होगा और उसी के तहत, कार्यकारी अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय निलंबित या पद से हटाया जा सकता है। धारा के इस भाग की भाषा में, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार किसी भी समय कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने या पद से हटाने के लिए अधिकृत है। सरकार को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं और इस धारा में यह नहीं कहा गया है कि इसके तहत कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार को संबंधित कार्यकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस या कोई अवसर देना होगा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह स्वीकार किया कि वह इस धारा के अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहा था। इसलिए, पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह मान लेना होगा कि धारा, जैसा कि तैयार किया गया है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद से प्रभावित नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क यह था कि भले ही धारा में कुछ भी उल्लेख नहीं है, लेकिन यह निहित है कि यदि राज्य सरकार कार्यकारी अधिकारी को या तो निलंबित करने या पद से हटाने जा रही है, तो उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का अवसर दिया जाएगा। उक्त सिद्धांत, तर्क आगे बढ़ता है, खंड में ही निहित है। निर्णय का मुद्दा यह है कि क्या ऐसा है।

(10) यदि इस उपधारा में, स्वयं विधान-मंडल ने यह उपबंध किया था कि राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने से पहले संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, तो क्या यह एक बुरा विधान होगा? याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसा ही होगा, लेकिन वह सैद्धांतिक रूप से या किसी निर्धारित मामले को उद्धृत करके अपने निवेदन का समर्थन करने में असमर्थ था। याचिकाकर्ता ने यह स्थिति नहीं ली कि पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम को लागू करना पंजाब विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर नहीं है। यह विषय निस्संदेह "राज्य सूची" द्वारा कवर किया गया था। वकील द्वारा यह भी इंगित नहीं किया जा सका कि यह कानून संविधान के किसी भी अनुच्छेद से प्रभावित होगा। किसी कानून को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अतः यह मान लेना चाहिए कि यदि विधान में स्वयं यह उल्लेख किया गया था कि इस उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध

कार्रवाई किए जाने से पूर्व उसे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा तो यह एक अच्छी विधि होगी और इसे निरस्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या विधायिका का यही इरादा धारा में उपयोग की गई भाषा में निहित नहीं है; क्योंकि अगर हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो विधायिका के लिए विशेष रूप से ऐसा कहना आवश्यक नहीं था। इस उप-धारा में उल्लिखित शब्द "किसी भी समय" विधानमंडल के इरादे का स्पष्ट संकेत देते हैं। इस अभिव्यक्ति का उपयोग करके, राज्य सरकार को किसी भी समय कार्यकारी अधिकारी को निलंबित या हटाने का अधिकार दिया गया था। यह सत्य है कि उपधारा (1) के अधीन यदि सरकार नगरपालिका समिति की सिफारिश को मंजूरी दे रही थी, तो कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए होगी। यह और भी सत्य है कि यदि नियुक्ति सरकार द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई थी तो नियुक्ति पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकती है। लेकिन उपधारा (7) उप-धारा (1) और (4) दोनों के तहत की गई नियुक्तियों को नियंत्रित करती है। दूसरे शब्दों में, इनमें से किसी भी उप-धारा के तहत नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी को सरकार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता था कि वह एक कार्यकाल की नौकरी थी। जब कोई कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति स्वीकार करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि भले ही नगर समिति उसे पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त कर रही थी, फिर भी सरकार को उसकी नियुक्ति के 15 दिनों के बाद भी उसे किसी भी समय हटाने का अधिकार था। इन परिस्थितियों में, वह शिकायत नहीं कर सकता है कि उसे पांच साल की पूरी अवधि के लिए पद का अधिकार था, और यदि वह जानता था कि उसकी सेवाएं किसी भी समय दी जा सकती हैं, तो उसे कोई शिकायत नहीं हो सकती है यदि राज्य सरकार द्वारा उसके खिलाफ उप-धारा (7) के तहत कार्रवाई की जाती है। वह यह नहीं कह सकते कि उन्हें क्यों और किस आधार पर हटाया जा रहा था और ठीक उसी कारण से वह यह भी नहीं कह सकते कि उन्हें उनके पद से हटाए जाने से पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, उसे पांच साल की पूरी अवधि के लिए पद का कोई अधिकार नहीं है, ताकि यदि उसे पहले हटा दिया जाता है, तो वह कारण बताओ नोटिस का हकदार है। उदाहरण के लिए, एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी का मामला लें। उन्हें इस पद का कोई अधिकार नहीं है और अगर उनकी सेवाएं 15 दिनों के बाद भी समाप्त कर दी जाती हैं, तो भी वे सरकार से यह नहीं कह सकते कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, मेरी राय में, केवल तभी लागू होते हैं जब किसी को किसी पद का अधिकार मिलता है और भले ही उसकी नियुक्ति की शर्तें यह नहीं कहती हैं कि उसकी सेवाओं को समाप्त करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, फिर भी उसे पद से बाहर जाने के लिए कहने से पहले इस तरह का नोटिस दिया जाना चाहिए। उस स्थिति में, उन्हें सरकार से यह पूछने का अधिकार है कि उनकी सेवाओं को क्यों छोड़ा जा रहा है। जब उन्होंने नियुक्ति स्वीकार की, तो उन्हें और सरकार दोनों को पता था कि उन्हें उस पद पर बने रहने का अधिकार है और अगर यह एक कार्यकाल की नौकरी है, तो दोनों पक्षों को पूरी तरह से एहसास हुआ कि उन्हें एक विशेष अवधि के लिए वहां रहना होगा। लेकिन, दूसरी ओर, यदि शुरुआत में ही उसे बताया जाता है कि यद्यपि उसे पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जा रहा है, फिर भी सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान उसकी सेवाओं को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, तो वह शिकायत नहीं कर सकता है कि उसकी सेवाओं को पहले क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि किस कारण से उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इस तरह की स्थिति में नहीं आते हैं। सरकार वैध रूप से उन्हें बता सकती है कि शुरुआत में ही उन्हें बताया गया था कि उन्हें बिना कोई कारण बताए किसी भी समय जाने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे कर्मचारी को क्या संभावित शिकायत हो सकती है? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को उनके द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह गंभीरता से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रत्येक मामले में आकर्षित होंगे और यह सिद्धांत सार्वभौमिक अनुप्रयोग का है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जब भी किसी भी प्रकार के कर्मचारी की सेवाएं दी जाती हैं, तो वह उस सिद्धांत के तहत शरण ले सकता है और कारण बताओ नोटिस की मांग कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही देखा है कि यदि किसी कर्मचारी को नियुक्ति स्वीकार करने से पहले ही शुरू में ही बताया जाता है कि उसकी सेवाएं सरकार की खुशी में हैं और उसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, तो उसे कोई शिकायत नहीं हो सकती है यदि सरकार उसे कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना उस शक्ति का प्रयोग करती है।

(11) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का मुख्य भरोसा डॉ. बूल चंद बनाम कुलाधिपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,ए.आई. आर. 1968 एस.सी. 292. में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर था। वहाँ कुलाधिपति (श्री

हाफिज मोहम्मद इब्राहिम) ने डॉ. 1 को नियुक्त किया। बूल चंद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में। 31 मार्च, 1966 को उस विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति एस. उज्ज्वल सिंह ने आदेश दिया कि डॉ. बूल चंद अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और उसके तुरंत बाद एक अन्य आदेश द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया जिसमें उन्हें कारण दिखाने की आवश्यकता थी कि कुलपति के रूप में उनकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया गया। डॉ. बूल चंद ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और उसके तुरंत बाद आदेश और कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के लिए मंडमस की प्रकृति में इस न्यायालय में एक याचिका दायर की। 8 मई, 1966 को कुलाधिपति ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की अनुसूची I की धारा 4 के उपखंड (vi) के तहत पंजाब सामान्य खंड अधिनियम, 1898 की धारा 14 के साथ पढ़ने की शक्ति का प्रयोग करते हुए डॉ. बूल चंद की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश पारित किया। डॉ. बूल चंद ने तब इस न्यायालय में अपनी याचिका में संशोधन किया और प्रमाण पत्र की एक रिट का भी दावा किया गया। इस अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और फिर मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया।

(12) उच्चतम न्यायालय में पहला तर्क यह दिया गया था कि कुलाधिपति के पास कुलपति के पद के कार्यकाल को समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं थी। खंड 4 के उपखंड (vi) और (vii) में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं:

"(vi) 'उप-कुलपति' की नियुक्ति 'कुलपति' (कुलाधिपति) द्वारा 'कुलपति' द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर की जाएगी।

(vii) 'उप-कुलपति' आम तौर पर तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके कार्यकाल का नवीनीकरण किया जा सकता है।"

(13) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम या उसके अधीन विधानों में ऐसा कोई स्पष्ट उपबंध नहीं था जो कुलपति के पद के कार्यकाल की समाप्ति से संबंधित था, लेकिन इस सिद्धांत पर कार्य करते हुए कि नियुक्ति करने की शक्ति सामान्य रूप से उसके साथ नियुक्ति निर्धारित करने की शक्ति रखती है और पंजाब सामान्य खंड अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों को भी लागू करती है, उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कुलाधिपति के पास कुलपति के पद के कार्यकाल को समाप्त करने की शक्ति थी।

(14) तब डॉ. बूल चंद की ओर से यह तर्क दिया गया कि कुलाधिपति अपने कार्यकाल का निर्धारण करने से पहले एक जांच करने के लिए बाध्य था और जांच प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप की जानी चाहिए थी। इस बिंदु पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा -

"यदि कुलपति की नियुक्ति ने नियुक्ति की शर्तों द्वारा शासित स्वामी और सेवक के संबंध को जन्म दिया, तो विशेष परिस्थितियों के अभाव में, उच्च न्यायालय अनुबंध की गलत समाप्ति की शिकायत करने वाले पक्ष को मुआवजे के मुकदमे में डाल देगा, और विश्वविद्यालय को कुलपति की सेवाओं को बनाए रखने के लिए मजबूर करने वाली उच्च विशेषाधिकार रिट जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा, जिसे विश्वविद्यालय सेवा में नहीं रखना चाहता है। लेकिन एक कुलपति का कार्यालय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा बनाया जाता है और उनकी नियुक्ति से कुलपति को अधिनियम के तहत वैधानिक शक्तियों और अधिकार के साथ निवेश किया जाता है। उच्च न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका एक भ्रमित दस्तावेज है। इस प्रकार अपीलार्थी ने दलील दी कि उसके और विश्वविद्यालय के बीच संबंध संविदात्मक था, लेकिन यह पूरी दलील नहीं थी। अपीलार्थी ने कुछ चौकसी के साथ यह भी अनुरोध किया कि चूंकि उन्हें कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया था, जो क़ानून द्वारा बनाया गया है, इसलिए उनकी नियुक्ति का कार्यकाल उन्हें यह समझाने का अवसर दिए बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अधिनियम, कानून और अध्यादेश उन शर्तों को निर्धारित नहीं करते हैं जिनमें कुलपति की नियुक्ति वह निर्धारित कर सकता है; और न ही अधिनियम नियुक्ति निर्धारित करने के लिए कुलाधिपति की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा निर्धारित करता है। लेकिन एक बार नियुक्ति एक क़ानून के अनुसरण में की जाती है, हालांकि नियुक्ति प्राधिकरण रोजगार का निर्धारण करने से

वंचित नहीं है, नियुक्ति प्राधिकरण का नियुक्ति को समाप्त करने का निर्णय केवल न्याय और निष्पक्षता की मूल अवधारणा के अनुरूप तरीके से आयोजित जांच के परिणाम के आधार पर हो सकता है।"

(15) मैंने उपरोक्त परिच्छेद को विस्तार से उद्धृत किया है, क्योंकि इन टिप्पणियों पर ही याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का पूरा तर्क आधारित था। उन्होंने विशेष रूप से उपरोक्त परिच्छेद में मेरे द्वारा रेखांकित पंक्तियों का उल्लेख किया और कहा कि कार्यकारी अधिकारी अधिनियम में भी ऐसी शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं जिनमें कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति निर्धारित की जा सकती है और न ही उस अधिनियम में कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमाएं निर्धारित की गई हैं। लेकिन एक बार जब किसी व्यक्ति को अधिनियम के अनुसरण में एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो तर्क आगे बढ़ता है, हालांकि राज्य सरकार उसके रोजगार का निर्धारण करने से वंचित नहीं है, नियुक्ति को समाप्त करने का राज्य सरकार का निर्णय केवल न्याय और निष्पक्षता की मूल अवधारणा के अनुरूप तरीके से आयोजित जांच के परिणाम पर आधारित होना चाहिए।

(16) इस तर्क में एक स्पष्ट भ्रांति है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम और उसके कानूनों और अध्यादेशों में यह उपबंध किया गया था कि कुलपति सामान्य रूप से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और उस कार्यकाल का नवीकरण किया जा सकता है, लेकिन यह कहीं भी निर्धारित नहीं किया गया था कि कुलाधिपति को उस अवधि के दौरान किसी भी समय अपने पद के कार्यकाल को समाप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था, जैसा कि कार्यकारी अधिकारी अधिनियम के तहत मामला है। यह दोनों मामलों में मुख्य अंतर है। वहां कुलपति को यह कहने के लिए दिया गया था कि वह सामान्य रूप से तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और स्वाभाविक रूप से, इसलिए, यदि उनके पद का कार्यकाल कम किया जा रहा था, तो वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत कारण बताओ नोटिस के हकदार थे और पूछते थे कि उनकी सेवाओं को पहले क्यों हटाया जा रहा था। हालांकि, वर्तमान मामले में, राज्य सरकार को किसी भी समय कार्यकारी अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति दी गई थी और उक्त अधिकारी को इस तथ्य के बारे में पूरी तरह से पता था और वह अच्छी तरह से जानता था जब उसने पद स्वीकार किया था, और इसलिए, उसे कोई नोटिस देने या उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के कारणों के बारे में सूचित करने का सवाल बिल्कुल भी नहीं उठा।

(17) डॉ. बूल चंद के मामले में, रिज बनाम बाल्डविन,1964 ए. सी 40. में लॉर्ड रीड की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद :

"इसलिए मैं पहले बर्खास्तगी के मामलों से निपटूंगा। ये तीन वर्गों में आते प्रतीत होते हैंः एक नौकर को उसके स्वामी द्वारा बर्खास्त करना, आनंद के दौरान आयोजित पद से बर्खास्त करना, और एक ऐसे पद से बर्खास्त करना जहां एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी बर्खास्तगी के लिए कुछ होना चाहिए। स्वामी और सेवक के बारे में कानून में कोई संदेह नहीं है। सेवा अनुबंध का कोई विशिष्ट स्वरूप नहीं हो सकता है, और स्वामी किसी भी समय और किसी भी कारण से या बिना किसी कारण के अपने नौकर के साथ अनुबंध को समाप्त कर सकता है। लेकिन अगर वह अनुबंध द्वारा वारंट नहीं किए गए तरीके से ऐसा करता है तो उसे अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने का भुगतान करना होगा। अतः स्वामी और सेवक के शुद्ध मामले में प्रश्न इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है कि स्वामी ने सेवक को अपने बचाव में सुना है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुकदमे में सामने आने वाले तथ्य अनुबंध का उल्लंघन साबित करते हैं या नहीं।

फिर ऐसे कई मामले हैं जहाँ एक आदमी खुशी से एक पद रखता है। न्यायाधीशों और अन्य लोगों के अलावा, जिनका कार्यकाल कानून द्वारा शासित होता है, क्राउन के सभी सेवक और अधिकारी खुशी से पद धारण करते हैं और यह एक औपनिवेशिक न्यायाधीश (टेरेल बनाम उपनिवेशों के लिए राज्य सचिव (1953) 2 क्यूबी 482) को लागू करने के लिए भी आयोजित किया गया है। यह हमेशा आयोजित किया गया है, मुझे लगता है कि सही है, और कारण स्पष्ट है। चूंकि बर्खास्तगी की शक्ति रखने वाले व्यक्ति के पास अधिकारी के खिलाफ कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए मैं तीसरी कक्षा में आता हूं, जिसमें वर्तमान मामला भी शामिल है। वहाँ मुझे अधिकार की एक अटूट रेखा मिलती है कि एक अधिकारी को पहले उसे बताए बिना कि उसके खिलाफ क्या आरोप लगाया गया है और उसके बचाव या स्पष्टीकरण को सुने बिना कानूनी रूप से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा -

"मामला या अपीलार्थी लॉर्ड रीड द्वारा बताए गए तीसरे दर्जे के दायरे में आता है, और उसके पद के कार्यकाल को पहले उसे सूचित किए बिना और उसे अपना बचाव या स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना बाधित नहीं किया जा सकता था।"

(18) यहां याचिकाकर्ता का मामला लॉर्ड रीड द्वारा उल्लिखित तीसरे वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अधिनियम की धारा 3 (7) के तहत उनके पद का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना किसी भी समय बाधित किया जा सकता है और जब उन्होंने नियुक्ति स्वीकार की और पद पर शामिल हुए तो उन्हें इस तथ्य की जानकारी थी।

(19) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तीन अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया-(i) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड और अन्य बनाम जाफर इमाम और अन्य ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 282. (ii) क्रिसा राज्य बनाम डॉ. (मिस) बिनापानी देई और अन्य ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1269. (6) 1969 एस.एल.आर. 445. और ए. के. क्राईपाक और, अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1969 एस.एल.आर.445।

(20) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड और अन्य के मामले में, डॉक श्रमिकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। उस मामले पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः

"जब अपीलकर्ता प्रतिवादी श्रमिकों के खिलाफ इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहता था कि वे कदाचार के दोषी हैं, तो अपीलकर्ता होर्ड टू रेव के लिए उचित जांच करना बिल्कुल आवश्यक था, जहां उचित था, उत्तरदाताओं को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कारण बताने का अवसर दिया जाना चाहिए था। जाँच में अपीलार्थी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध साक्ष्य का नेतृत्व करने और उन्हें उक्त साक्ष्य का परीक्षण करने का उचित मौका देने के लिए बाध्य था; उन्हें बचाव में साक्ष्य का नेतृत्व करने की स्वतंत्रता दें, और फिर अपने स्वयं के निर्णय पर आएं। न केवल प्राकृतिक न्याय की अपेक्षाओं द्वारा ऐसी जांच निर्धारित की गई थी, बल्कि 1951 की योजना के खंड (36) (3) और 1956 की योजना के खंड 45 (6) द्वारा अपीलार्थी पर ऐसी जांच करने का दायित्व भी लगाया गया था।"

यह मामला याचिकाकर्ता के लिए कोई सहायक नहीं है। वहां केंद्र सरकार द्वारा डॉक वर्कर्स (रोजगार विनियमन) अधिनियम (IX of 1948) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह योजना बनाई गई थी, खंड (36) अनुशासनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है और उपखंड (3) में यह निर्धारित किया गया है कि कोई कार्रवाई करने से पहले संबंधित व्यक्ति को यह कारण दिखाने का अवसर दिया जाना चाहिए कि उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसका मतलब यह था कि योजना के लिए यह आवश्यक था कि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले उसे कारण बताने का अवसर दिया जाए। कार्यकारी अधिकारी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(21) डॉ. बिनापानी देई के मामले में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जन्म की एक निश्चित विवादित तिथि पर आधारित था। याचिकाकर्ता की सही जन्म तिथि का पता लगाने के लिए जांच की गई थी, लेकिन उसे जांच अधिकारी की रिपोर्ट नहीं दी गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उस मामले का निपटारा करते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक प्रशासनिक आदेश, जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हैं, को भी प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। कानून के उस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, उस फैसले के तथ्य वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं।

(22) ए. के. क्राईपक और अन्य के मामले में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्राकृतिक न्याय के नियम प्रशासनिक जांचों पर भी लागू होते हैं, उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना या इसे नकारात्मक रूप में रखना न्याय की विफलता को रोकने के लिए था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, वे नियम केवल उन क्षेत्रों में ही काम कर सकते हैं जो वैध रूप से बनाए गए किसी कानून के दायरे में नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने देश के कानून का स्थान नहीं लिया, बल्कि इसे पूरक बनाया। इस प्राधिकरण के अनुसार, यदि कोई कानून नहीं बनाया गया तो प्राकृतिक न्याय के नियम काम करेंगे। लेकिन हाथ में मामले में, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, अधिनियम की धारा 3 (7) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राज्य सरकार को किसी भी समय कार्यकारी अधिकारी को निलंबित करने या हटाने का पूरी तरह से अधिकार था और उस शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इस विशिष्ट कानून के सामने, याचिकाकर्ता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू नहीं कर सका और अपनी सेवाओं को समाप्त करने से पहले कारण बताओ नोटिस का दावा नहीं कर सका। इसलिए यह निर्णय भी याचिकाकर्ता के लिए कोई मददगार नहीं है।

(23) जो मैंने ऊपर कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है। ऐसा होने पर, हमें संदर्भित दूसरा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

एस. एस. संधवालिया, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ।

भूपिंदर सिंह ढिल्लों, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा